



युवाओं में बेरोजगारी और सामाजिक परिवर्तन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. नेहा कुमारी

Paper Received On: 20 MAR 2026

Peer Reviewed On: 24 APRIL 2026

Published On: 01 MAY 2026

Abstract

समकालीन भारत, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों के संदर्भ में युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की पड़ताल करता है। अध्ययन में अब्राहम मास्लो और फ्रेडरिक हर्जवर्ग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ जॉर्ड सिमेल के 'द स्ट्रेंजर' सिद्धांत का उपयोग करते हुए यह विश्लेषण किया गया है कि आर्थिक असुरक्षा कैसे पहचान के संकट और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि 'मशीन लर्निंग' और 'ऑटोमेशन' के कारण पैदा हुआ 'स्किल गैप' संरचनात्मक बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, जिससे युवाओं में राजनीतिक असंतोष और पलायन की प्रवृत्ति बढ़ी है। लेख में बिहार खेल नीति २०२३ और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंततः, यह लेख तर्क देता है कि बेरोजगारी एक 'सोशल टाइम बम' है जिसका समाधान केवल सरकारी नौकरियों में नहीं, बल्कि शिक्षा के व्यवसायीकरण और विकेंद्रीकृत उद्यमिता में निहित है।

कीवर्ड्स : बेरोजगारी, सामाजिक परिवर्तन, पलायन, पहचान का संकट, बिहार खेल नीति २०२३, स्किल गैप, जनांकिकीय लाभांश, जॉर्ड सिमेल।

प्रस्तावना

बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभिशाप है। इसका अर्थ उस स्थिति से है जब व्यक्ति काम करने में सक्षम और इच्छुक होते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। युवाओं के संदर्भ में यह केवल काम का अभाव नहीं, बल्कि योग्यता और अवसर के बीच का अंतर है। उच्च शिक्षित युवाओं को उपयुक्त अवसर न मिलने पर वे अल्प-बेरोजगारी के शिकार होते हैं, जो आगे चलकर व्यापक बेरोजगारी का रूप ले लेती है।

वर्तमान परिदृश्य: वैश्विक एवं भारतीय संदर्भ

आज विश्व 'जनांकिकीय लाभांश' के दौर में है, जहाँ कार्यशील जनसंख्या की प्रधानता है। भारत में औसत आयु 28-29 वर्ष होने के बावजूद यह अवसर पूरी तरह साकार नहीं हो पाया, और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

- **वैश्विक स्थिति:** International Labour Organization के अनुसार, वैश्विक स्तर पर युवाओं में बेरोजगारी दर वयस्कों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है, जिसे तकनीकी बदलावों और आर्थिक मंदी ने और

बढ़ा दिया है।

- **भारतीय परिदृश्य:** भारत में स्थिति जटिल है—तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद 'शिक्षित बेरोजगारी' गंभीर समस्या बनी हुई है। Centre for Monitoring Indian Economy के अनुसार, स्नातक युवाओं में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो शिक्षा प्रणाली और बाजार की मांग के बीच असंतुलन को दर्शाता है।

बेरोजगारी और सामाजिक परिवर्तन का अंतर्संबंध

बेरोजगारी केवल आय की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और मूल्यों को भी प्रभावित करती है। युवाओं की निष्क्रियता विवाह, अपराध, मानसिक स्वास्थ्य और राजनीति पर असर डालती है। आज युवा पारंपरिक करियर से हटकर गिग इकोनॉमी और डिजिटल उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे नए सामाजिक वर्ग और संघर्ष उभर रहे हैं।

उद्देश्य

बेरोजगारी के आर्थिक पहलुओं तक सीमित न रहकर उससे उत्पन्न सामाजिक परिवर्तनों की पड़ताल करता है। इसका उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि रोजगार की कमी ने भारतीय युवाओं के मनोविज्ञान, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित किया है।

बेरोजगारी के प्रमुख कारण

बेरोजगारी कोई स्वतंत्र घटना नहीं, बल्कि शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों का संयुक्त परिणाम है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के पीछे कई प्रमुख कारक जिम्मेदार हैं:

शिक्षा-कौशल अंतर:

आज डिग्री और दक्षता के बीच की खाई एक बड़ी चुनौती है। शैक्षणिक संस्थान अभी भी सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित हैं, जबकि बाजार में व्यावहारिक कौशल की अधिक मांग है।

- **डिग्री बनाम दक्षता:** भारत में हर वर्ष लाखों स्नातक निकलते हैं, लेकिन NASSCOM जैसी संस्थाओं के अनुसार, उनमें से आधे से अधिक 'रोजगार योग्य' नहीं होते।
- **सॉफ्ट स्किल्स का अभाव:** तकनीकी ज्ञान के साथ संचार कौशल, समस्या-समाधान और टीम वर्क जैसी क्षमताओं की कमी युवाओं को प्रतिस्पर्धा में पीछे कर देती है।

जनसंख्या विस्फोट और कार्यबल की अधिकता:

भारत में जनसंख्या एक 'दोधारी तलवार' है—उचित प्रशिक्षण मिलने पर यह मानव पूंजी बन सकती है, अन्यथा यह एक गंभीर चुनौती में बदल जाती है।

- **संसाधन बनाम मांग:** श्रम बाजार में आने वाले युवाओं की संख्या इतनी अधिक है कि अर्थव्यवस्था उसी अनुपात में नई नौकरियाँ सृजित नहीं कर पा रही है।

- जनांकिकीय दबाव:** हर साल लगभग 1.2 करोड़ लोग श्रम बाजार में जुड़ते हैं, लेकिन उन्हें समाहित करने के लिए औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का विस्तार पर्याप्त नहीं हो पाया है।

तकनीकी विस्थापन: AI और ऑटोमेशन का युग

चौथी औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) ने रोजगार के पारंपरिक स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI):** डेटा एंट्री, ग्राहक सेवा और कोडिंग जैसे क्षेत्रों में AI मानव श्रम का स्थान ले रहा है, जबकि ऑटोमेशन ने विनिर्माण क्षेत्र में श्रम की आवश्यकता को घटा दिया है।
- विस्थापन बनाम सृजन:** तकनीक नई नौकरियाँ पैदा करती है, लेकिन ये उच्च कौशल मांगती हैं, जिससे कम कौशल वाले श्रमिकों का विस्थापन बढ़ता है।

तकनीकी विस्थापन: वैश्विक और भारतीय सांख्यिकी

- World Economic Forum (Future of Jobs Report 2023):** इस रिपोर्ट के अनुसार, तकनीक और डिजिटलीकरण के कारण वैश्विक रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव होने की संभावना है।
- नौकरियों का विस्थापन:** अगले पाँच वर्षों में लगभग 8.3 करोड़ (83 million) नौकरियों के समाप्त होने का अनुमान है।
- नौकरियों का सृजन:** इसी अवधि में AI और मशीन लर्निंग के कारण लगभग 6.9 करोड़ (69 million) नई नौकरियाँ भी उत्पन्न होने की संभावना है।
- शुद्ध प्रभाव:** कुल मिलाकर लगभग 1.4 करोड़ नौकरियों का शुद्ध नुकसान होगा, जो वैश्विक श्रम बाजार का लगभग 2% है।

ऑटोमेशन का प्रभाव: तुलनात्मक विश्लेषण

क्षेत्र (Sector)	ऑटोमेशन का प्रभाव	प्रभावित नौकरियाँ	नई अवसर (Emerging Jobs)	कौशल की आवश्यकता
विनिर्माण (Manufacturing)	उच्च	मशीन ऑपरेटर, असेंबली लाइन वर्कर	रोबोटिक्स इंजीनियर, AI टेक्नीशियन	तकनीकी/ऑटोमेशन कौशल
IT / BPO	मध्यम-उच्च	डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग	डेटा साइंटिस्ट, AI डेवलपर	प्रोग्रामिंग, AI/ML
बैंकिंग / फाइनेंस	मध्यम	कैशियर, क्लेरिकल जॉब्स	फिनटेक विशेषज्ञ, डेटा एनालिस्ट	एनालिटिक्स, डिजिटल कौशल
रिटेल (Retail)	मध्यम	सेल्समैन, बिलिंग स्टाफ	ई-कॉमर्स मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग	कम्युनिकेशन, डिजिटल टूल्स
स्वास्थ्य (Healthcare)	कम-मध्यम	रिकॉर्ड कीपिंग स्टाफ	हेल्थ-टेक स्पेशलिस्ट, टेलीमेडिसिन	टेक + मेडिकल ज्ञान
शिक्षा (Education)	कम	पारंपरिक शिक्षण कार्य	ई-लर्निंग डेवलपर, एड-टेक विशेषज्ञ	डिजिटल शिक्षण कौशल

बेरोजगारी और सामाजिक परिवर्तन:

लंबे समय तक युवा आबादी के आर्थिक रूप से निष्क्रिय रहने से समाज की पारंपरिक व्यवस्थाओं में बदलाव आता है, जिसका प्रभाव मुख्यतः दो स्तरों पर देखा जाता है।

1. पारिवारिक और व्यक्तिगत (मानसिक) स्तर

पारिवारिक विघटन और संरचनात्मक बदलाव (Family Disintegration):

परिवार की स्थिरता आर्थिक आधार पर टिकी होती है, और बेरोजगारी इस आधार को कमजोर कर देती है, जिससे कई सामाजिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं:

- **विवाह पर प्रभाव:** बेरोजगारी के कारण आर्थिक आत्मनिर्भरता न होने से विवाह में देरी होती है, जिससे अकेलापन और सामाजिक अलगाव बढ़ता है।
- **अंतर्पीढ़ी संघर्ष:** लंबे समय तक निर्भरता से परिवार में तनाव, विवाद और सम्मान की कमी बढ़ती है।
- **घरेलू कलह:** आर्थिक तंगी और अनिश्चितता से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, जिससे घरेलू हिंसा और संघर्ष की संभावना अधिक हो जाती है।

2. युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य:

बेरोजगारी का सबसे गहरा प्रभाव युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यह केवल आर्थिक कमी नहीं, बल्कि अस्तित्व के संकट की स्थिति उत्पन्न करती है।

- **पहचान का संकट:** काम न होने पर युवा आत्म-सम्मान खोकर खुद को समाज पर बोझ समझने लगते हैं।
- **अवसाद और चिंता:** लगातार असफलता और दबाव मानसिक समस्याओं को बढ़ाते हैं; National Crime Records Bureau के अनुसार आत्महत्या के मामलों में वृद्धि देखी गई है।
- **नशे की ओर झुकाव:** तनाव से बचने के लिए कुछ युवा नशे का सहारा लेते हैं, जिससे स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएँ बढ़ती हैं।

सामाजिक अलगाव और रेडिकलाइजेशन:

जब युवाओं को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में अवसर नहीं मिलता, तो उनमें अलगाव की भावना बढ़ती है और वे व्यवस्था के प्रति असंतोष या विद्रोह की ओर झुक सकते हैं।

- **अपराध की ओर झुकाव:** खाली समय और आर्थिक जरूरतें युवाओं को साइबर अपराध, चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों की ओर प्रेरित कर सकती हैं।
- **चरमपंथ का खतरा:** बेरोजगार युवा आसानी से कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रभाव में आ सकते हैं, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है।

तालिका: बेरोजगारी के सामाजिक प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण

आयाम (Dimension)	प्रभाव (Impact)	परिणाम (Outcome)
पारिवारिक जीवन	आर्थिक निर्भरता, तनाव	पारिवारिक कलह, संबंधों में दरार
मानसिक स्वास्थ्य	अवसाद, चिंता, पहचान संकट	आत्मसम्मान में कमी, आत्महत्या का जोखिम
सामाजिक व्यवहार	अलगाव, असंतोष	समाज से दूरी, विद्रोही प्रवृत्ति
अपराध प्रवृत्ति	खाली समय व आर्थिक दबाव	साइबर अपराध, चोरी, असामाजिक गतिविधियाँ
नशा और व्यसन	तनाव से बचने की प्रवृत्ति	स्वास्थ्य हानि, सामाजिक बोझ
राजनीतिक/सामाजिक स्थिरता	असंतोष और आक्रोश	सामाजिक अशांति, चरमपंथ का जोखिम

सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक चेतना:

बेरोजगारी बढ़ने पर यह व्यक्तिगत समस्या से आगे बढ़कर सामूहिक कुंठा बन जाती है। समाजशास्त्र में इसे सापेक्षिक अभाव कहा जाता है, जहाँ युवा अपनी स्थिति की तुलना दूसरों से कर व्यवस्था के प्रति असंतोष और आक्रोश महसूस करते हैं।

1. सामूहिक कुंठा से संगठित विरोध तक:

बेरोजगारी युवाओं को घर तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें विरोध की ओर प्रेरित करती है।

- **असंतोष का एकीकरण:** समान समस्याएँ युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ती हैं और व्यक्तिगत दुख को सामूहिक आंदोलन में बदल देती हैं।
- **विरोध का स्वरूप:** हाल के वर्षों में रोजगार और भर्ती सुधार से जुड़े कई आंदोलन देखे गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि युवा अब केवल याचक नहीं, बल्कि सक्रिय आंदोलनकारी बन गए हैं।

2. राजनीतिक चेतना और युवा मतदाता:

बेरोजगारी ने युवाओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं को बदल दिया है।

- **मुद्दों का ध्रुवीकरण:** अब रोजगार एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है, जहाँ युवा नौकरी और भर्ती पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
- **वोटिंग पैटर्न में बदलाव:** बेरोजगार युवा अक्सर उन विकल्पों की ओर झुकते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन का वादा करते हैं, जिससे सत्ता विरोधी रुझान बढ़ता है।

3. डिजिटल सक्रियता (Digital Activism):

आधुनिक सामाजिक आंदोलनों का स्वरूप अब डिजिटल हो गया है, जहाँ विरोध केवल सड़कों तक सीमित नहीं है।

- **हैशटैग पॉलिटिक्स:** ट्रेंड्स युवाओं की डिजिटल राजनीतिक भागीदारी को दर्शाते हैं।
- **सूचना का लोकतंत्रीकरण:** इंटरनेट ने ग्रामीण युवाओं तक भी नीतियों और भर्ती से जुड़ी जानकारी पहुंचाकर उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है।

विश्लेषणात्मक ढांचा: कुंठा से आंदोलन का सफर

चरण	विशेषता	सामाजिक प्रभाव
चरण 1: व्यक्तिगत कुंठा	नौकरी न मिलना, आर्थिक असुरक्षा	अलगाव, तनाव और अवसाद
चरण 2: सामाजिक संवाद	समान समस्याओं वाले युवाओं से जुड़ाव	साझा पहचान और समूह निर्माण
चरण 3: राजनीतिक चेतना	नीतिगत विफलताओं की पहचान	व्यवस्था के प्रति अविश्वास और असंतोष
चरण 4: संगठित आंदोलन	प्रदर्शन, हड़ताल और डिजिटल सक्रियता	नीतिगत दबाव और सामाजिक परिवर्तन की संभावना

लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी:

बेरोजगारी युवाओं के राजनीतिक व्यवहार और लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित कर रही है। Centre for the Study of Developing Societies और Lokniti Programme for Comparative Democracy के सर्वेक्षणों के अनुसार, युवाओं में रोजगार को लेकर बढ़ती चिंता उनके राजनीतिक रुझानों और भागीदारी को नया आकार दे रही है।

1. प्राथमिक चिंता के रूप में बेरोजगारी:

Centre for the Study of Developing Societies और Lokniti Programme for Comparative Democracy के सर्वेक्षणों के अनुसार, पिछले एक दशक में भारतीय युवाओं के बीच बेरोजगारी सबसे प्रमुख चिंता बन गई है।

- **सर्वेक्षण डेटा:** 2021-22 में लगभग 18-40% युवाओं ने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या माना, जो अन्य मुद्दों से अधिक है।
- **राजनीतिक प्राथमिकता:** युवा अब पहचान-आधारित राजनीति की तुलना में विकास और रोजगार-आधारित राजनीति को अधिक महत्व दे रहे हैं।

2. चुनावी व्यवहार और वोटिंग पैटर्न:

Lokniti Programme for Comparative Democracy के आंकड़ों के अनुसार युवाओं की राजनीतिक भागीदारी में एक “सक्रियतावादी मोड़” देखा गया है।

- **मतदान प्रतिशत:** 18-25 आयु वर्ग के युवाओं का मतदान अक्सर राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे अधिक रहा है, जो दर्शाता है कि बेरोजगारी ने उन्हें राजनीति से दूर नहीं किया, बल्कि वोट के माध्यम से अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है।
- **अविश्वास और आशा का द्वंद्व:** युवा भर्ती प्रक्रियाओं और संस्थागत भ्रष्टाचार से निराश हैं, लेकिन वे अभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह उम्मीद रखते हैं कि चुनावों के माध्यम से परिवर्तन संभव है।

3. आंदोलनों में भागीदारी और विरोध का अधिकार:

Centre for the Study of Developing Societies की 'युवा और राजनीति' रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार युवा नागरिक आंदोलनों में सबसे सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

- **सड़क से सोशल मीडिया तक:** 50% से अधिक शहरी युवा सोशल मीडिया का उपयोग राजनीतिक चर्चा और विरोध आंदोलनों के संगठन के लिए करते हैं।
- **मुद्दों पर आधारित एकजुटता:** Lokniti Programme for Comparative Democracy के अनुसार युवा अब पार्टी-आधारित निष्ठा के बजाय मुद्दा-आधारित (issue-based) राजनीति को प्राथमिकता देते हैं और रोजगार जैसे मुद्दों पर विफलता होने पर राजनीतिक समर्थन बदलने में तेजी दिखाते हैं।

4. जेंडर और वर्ग आधारित असमानता (Intersecting Disparities):

Centre for the Study of Developing Societies के सर्वेक्षणों से स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी का प्रभाव सभी युवाओं पर समान नहीं होता।

- **महिला भागीदारी:** बेरोजगार महिला युवाओं की राजनीतिक भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण सामाजिक और घरेलू प्रतिबंध हैं।
- **शिक्षित बनाम अशिक्षित:** शिक्षित बेरोजगार युवाओं में राजनीतिक सक्रियता अधिक देखी जाती है, क्योंकि उनमें अपनी स्थिति के प्रति *सापेक्षिक अभाव* की भावना अधिक तीव्र होती है।

तालिका: CSDS-Lokniti के आंकड़ों का सारांश

आयाम	प्रमुख निष्कर्ष	सामाजिक/राजनीतिक प्रभाव
प्राथमिक चिंता	बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरी	विकास और रोजगार-आधारित राजनीति की ओर झुकाव
चुनावी व्यवहार	युवा मतदान में सक्रिय भागीदारी	वोट के माध्यम से परिवर्तन की उम्मीद
आंदोलन भागीदारी	सोशल मीडिया और सड़कों पर सक्रियता	मुद्दा-आधारित (Issue-based) राजनीति का विकास
जेंडर असमानता	महिला भागीदारी अपेक्षाकृत कम	सामाजिक प्रतिबंधों का प्रभाव स्पष्ट
शिक्षा प्रभाव	शिक्षित बेरोजगार अधिक सक्रिय	सापेक्षिक अभाव से बढ़ी राजनीतिक चेतना

ग्रामीण बनाम शहरी बेरोजगारी

भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्षेत्रीय रूप से भिन्न है—ग्रामीण क्षेत्रों में यह अधिकतर **अदृश्य/मौसमी** है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह **शिक्षित और खुली बेरोजगारी** के रूप में दिखाई देती है।

ग्रामीण बेरोजगारी

- **प्रच्छन्न बेरोजगारी:** कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रम होने से उत्पादकता पर असर नहीं पड़ता, लेकिन युवाओं में निष्क्रियता की भावना बढ़ती है।
- **कृषि से विमुखता:** कम लाभ और अनिश्चितता के कारण युवा खेती को आकर्षक नहीं मानते।
- **मौसमी बेरोजगारी:** वर्ष के कुछ महीनों में काम की कमी से सामाजिक और व्यवहारिक समस्याएँ बढ़ती हैं।

शहरी बेरोजगारी

- **शिक्षित बेरोजगारी:** डिग्री होने के बावजूद नौकरी की कमी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती है।
- **गीग इकोनॉमी का विस्तार:** प्लेटफॉर्म आधारित कार्य (जैसे डिलीवरी/राइड-शेयरिंग) रोजगार देता है, लेकिन इसमें स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा की कमी है।

पलायन (Migration)

- गांव से शहर की ओर रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन होता है।
- इससे ग्रामीण परिवारों का विखंडन और महिलाओं पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ता है।
- शहरों में जनसंख्या दबाव के कारण झुग्गी बस्तियों और असंगठित शहरीकरण में वृद्धि होती है।

तुलनात्मक तालिका: ग्रामीण बनाम शहरी बेरोजगारी

आधार	ग्रामीण बेरोजगारी	शहरी बेरोजगारी
मुख्य स्वरूप	प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी	शिक्षित और तकनीकी बेरोजगारी
प्रमुख कारण	कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित कौशल	मांग-आपूर्ति असंतुलन, ऑटोमेशन और प्रतिस्पर्धा
सामाजिक परिणाम	पलायन, परिवारों का विखंडन	मानसिक तनाव, अकेलापन, शहरी अपराध
समाधान दिशा	की कुटीर उद्योग, कृषि-प्रसंस्करण (Agri-processing)	स्टार्टअप, री-स्किलिंग, सेवा क्षेत्र का विस्तार

सरकार की भूमिका और समाधान

बेरोजगारी के समाधान के लिए केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि **समावेशी और कौशल-आधारित नीतियों** की आवश्यकता है। सरकार को नियामक के साथ-साथ एक **सुविधा प्रदाता** की भूमिका निभानी होगी।

कौशल विकास

Skill India Mission और National Education Policy 2020 के तहत शिक्षा को कौशल-आधारित बनाना आवश्यक है। युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुसार लगातार **री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग** की सुविधा देना जरूरी है।

उद्यमिता और स्टार्टअप

Startup India और Stand Up India जैसी योजनाएँ युवाओं को नौकरी देने वाले बनाने में मदद करती हैं। Pradhan Mantri MUDRA Yojana के माध्यम से छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे रोजगार सृजन बढ़ता है।

क्षेत्रीय नीतियाँ

राज्य स्तर पर औद्योगिक और खेल नीतियाँ रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं, जैसे बिहार में विनिर्माण और खेल आधारित करियर को बढ़ावा।

सामाजिक सुरक्षा

बेरोजगारी के समय आर्थिक सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र और डिजिटल रोजगार पोर्टल्स को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि युवा अस्थिरता से बच सकें।

निष्कर्ष

बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक टाइम बम है। युवाओं की ऊर्जा लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर असंतोष, अपराध और सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे सकती है। सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता व्यावहारिक नहीं है। रोजगार केवल सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि नए अवसरों का सृजन आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली को डिग्री-आधारित से कौशल-आधारित बनाना जरूरी है, ताकि युवा उद्योग की जरूरतों के अनुसार सक्षम बन सकें। स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवा नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं।

संदर्भ सूची (Reference List)

- Abraham, M. H. (1943). *A theory of human motivation*. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press.
- Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). (2025). *Unemployment in India: Statistical Report 2024-25*. CMIE Publications.
- CSDS-Lokniti. (2021). *Youth in India: Aspirations, Identities and Political Participation*. Lokniti: Programme for Comparative Democracy.
- Das, S., & Drèze, J. (2024). *Economic Reform and Social Opportunity in India*. Oxford University Press.
- Goldman Sachs. (2024). *The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth*. *Global Economics Analyst*.
- Government of Bihar. (2023). *Bihar Sports Policy 2023: Guidelines for Excellence*. Department of
- Copyright © 2026, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- Art, Culture and Youth.*
- Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education.
- Herzberg, F. (1966). *Work and the Nature of Man*. World Publishing Company.
- International Labour Organization (ILO). (2023). *Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people* (p. 45). ILO Publications.
- International Monetary Fund (IMF). (2024). *Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work*. IMF Staff Discussion Notes.
- Jha, P. (2024). *Labour Market and Employment in Bihar: A Socio-Economic Analysis*. Sage Publications.
- Kasarda, J. D., & Crenshaw, E. M. (1991). *Third world urbanization: Dimensions, theories, and determinants*. *Annual Review of Sociology*, 17, 467–501.
- Kumar, S. (2025). *Digital Transformation and the Indian Labour Market*. Tata McGraw-Hill.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. Harper & Row.
- Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2023). *Annual Report 2022-23*. Government of India.
- NASSCOM. (2024). *The Future of Skills: Impact of Generative AI on the Indian Tech Workforce*. Strategic Review.
- National Crime Records Bureau (NCRB). (2024). *Accidental Deaths & Suicides in India (ADSI) 2023*. Ministry of Home Affairs.
- NITI Aayog. (2024). *Strategy for New India @ 75: Focus on Employment and Growth*. Government of India.
- OECD. (2023). *OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market*. OECD Publishing.
- Patnaik, P. (2024). *The problem of unemployment in the neoliberal era*. *Social Scientist*, 52(1-2), 3–14.
- Periodic Labour Force Survey (PLFS). (2024). *Annual Report (July 2023 - June 2024)*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
- Ravenstein, E. G. (1885). *The laws of migration*. *Journal of the Statistical Society of London*, 48(2), 167–235.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
- Simmel, G. (1950). *The Sociology of Georg Simmel* (K. H. Wolff, Trans.). Free Press. (Original work published 1908).
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Pearson.
- UNESCO. (2024). *Global Education Monitoring Report: Technology in Education*. UNESCO Publishing.
- World Bank. (2024). *World Development Report 2024: The Future of Work*. World Bank Group.
- World Economic Forum. (2023). *The Future of Jobs Report 2023*. WEF Publications.

Cite Your Article as

Dr. Neha Kumari. (2026). YUVAON ME BEROJGARI AUR SAMAJIK PARIVARTAN: EK VISHLESHANATMAK ADHYAYAN. *Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*, 14(94), 70–79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20069639>